

पहले मुख्य समाचार।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के प्रति दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता, कहा- धन धान्य कृषि योजना से पिछड़े जिलों में बढ़ेगा फसल उत्पादन।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी, देश के एक करोड़ सत्तर लाख किसानों की होगी मदद।
- दस लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण दिलवाएगी सरकार, ग्राम स्तरीय उद्यमियों को मिलेगी वरीयता।
- प्रदेश में आपदा प्रबंधन को अतिरिक्त प्रभावी, समन्वित, वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-यूएनडीपी के साथ किया गया एमओयू।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से देश के एक करोड़ सत्तर लाख किसानों को मदद मिलेगी। योजना के तहत देश में सौ जिलों की पहचान की जाएगी।

सौ ऐसे जिले जिसमें कृषि पर तीन पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो ऐसे सौ जिलों को चयनित करके। उसमें एक फोकस्ड वे में ग्यारह मंत्रालयों के छत्तीस स्कीम इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करे ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय उत्पादकता में प्रगति और फसलों में विविधता के साथ ही दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाएगा।

प्रदेश के किसानों में योजना को लेकर विशेष प्रसन्नता है। चित्रकूट के किसान अजीत सिंह ने इस फैसले के लिये प्रधानमंत्री का आभार जताया है।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पीएम धन-धान्य योजना को मंजूरी दी गयी है। हम इसके लिए तहेदिल से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इससे बुंदेलखंड के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा-निर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड-एनएलसीआईएल के लिए विशेष छूट को भी मंजूरी दे दी। इस छूट का उद्देश्य वर्ष दो हजार तीस तक दस गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के एनएलसीआईएल के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्ताव में कैबिनेट ने इसे गर्व, गौरव और उल्लास का विषय बताया।

कैबिनेट के प्रस्ताव पर लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला और मां आशा शुक्ला ने खुशी जताई है। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने प्रस्ताव पारित किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।

हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने जो है बच्चे के लिए हमारे जो है आभार व्यक्त किया उनके प्रयास के बिना ये मिशन संभव नहीं था। उनके प्रयास से ही जो है संभव हो पाया।

नीति आयोग द्वारा 'विकसित राज्य फॉर विकसित भारत दो हजार सैंतालीस' कार्यक्रम के तहत कल लखनऊ योजना भवन में "विकसित यूपी दो हजार सैंतालीस" विषय पर एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रह्मण्यम् ने की। इस अवसर पर विकसित भारत दो हजार सैंतालीस' के

राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत उत्तर प्रदेश के संभावित विकास मार्गों और प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा की गई। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी शामिल हुए।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नेशनल एक्शन फॉर मेकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम- नमस्ते दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नमस्ते हेल्प लाइन नंबर की शुरुआत भी की।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश के दस लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली के यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में डिजिटल इंडिया के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'सीएससी दिवस' कार्यक्रम में यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने सामान्य सेवा केंद्र-सीएससी कार्यकर्ताओं के प्रयासों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे देश के ग्राम स्तरीय उद्यमियों ने डिजिटल इंडिया का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाकर एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

प्रदेश में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित, वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी के मध्य कल एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूएनडीपी की भारत प्रमुख तथा रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंजेला लुसीगी की मौजूदगी में हुआ यह समझौता प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रमों को लागू करने, राज्य की संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाने और बहुस्तरीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था को तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में कुल उन्नीस करोड़ निम्नयानबे लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह साझेदारी राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को विश्वस्तरीय बनाएगी और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन की दिशा में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा।

बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और सहायता के लिए प्रदेश के सभी जिलों में आज से उन्नीस जुलाई तक उपभोक्ता मेगा कैम्प लगाए जाएंगे। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक ये मेगा कैम्प अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर आयोजित होंगे। यहां उपभोक्ता बिजली बिल में सुधार, नए कनेक्शन, भार बढ़ोतरी, मीटर संबंधी शिकायतों का समाधान कराने के साथ बिल भुगतान में सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदेश में कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद और मेरठ में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तेईस जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने बताया कि स्कूलों को सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बंद किया गया है।

बच्चों की सुरक्षा और उनके साथ जो और है उनके पेरेंट्स की सुरक्षा भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तेईस तक स्कूल और जितने शैक्षणिक संस्था है उन सबको अध्यातन सुरक्षा के दृष्टिगत शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बंद कर दिया गया है।

कांवड़ यात्रा के चलते विभिन्न जिलों में रूट डायवर्जन और भीड़ को देखते हुए डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने सत्र दो हजार चौबीस पचीस की सम सेमेस्टर द्वितीय चरण की परीक्षाएं भी तेईस जुलाई तक स्थागित कर दी हैं। इन परीक्षाओं की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी।

प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बलिया जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मीरजापुर जिले में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से प्रयागराज के निचले क्षेत्रों में घरों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में आज भी कहीं कहीं भारी वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।
